There is an urgent matter. I would request Dr. U. Venkateswarlu to lay the papers.

TREATY BETWEEN INDIA AND BANGLADESH ON SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri I.K. Gujral, I beg to lay on the Table of the House a copy each (in Hindi and English) of the treaty between India and Bangladesh on sharing of the Ganga Waters at Farakka as mentioned in the Statement which was made in the House today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): As you know Shri I.K. Gujaral has already stated in the House that clarifications will be made tomorrow. So all the clarifications will be taken up tomorrow. I want to take the sense of the House. There are four other Members to speak on the Bill and there are Special Mentions also.

श्री राम देव भंडारी (बिहार): स्पेशल मैंशन कल, यह बिल आज कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): यह डी०डी०ए० वाला बिल आज पूरा कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): ठीक है। भंडारी जी, आप शुरु कीजिए।

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 1996—Contd.

श्री राम देव भंडारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि दिल्ली में जो झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जे० जे० कालोनी हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों महेन्द्र यादव, एडवोकेट के नेतृत्व में जंतर-मंतर के पास हजारों लोगों ने 49 दिनों तक धरना दिया था। हमारे मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जी वहां गए थे और एक डेलीगेशन को लेकर उन्होंने प्राइम-मिनिस्टर साहब से भी बात की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में जो उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे।

5.00 म० प०

मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये जो कालोनियां हैं, इनको शीघ्र नियमित किया जाए। सरकार द्वारा वहां मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इन सारी बातों की भी व्यवस्था की जाए ताकि वे लाखों-लाख लोग जो वहां नर्क की जिन्दगी बिता रहे हैं, उनको उस जिन्दगी से उबारा जा सके।

महोदय, 1989 में जब वी० पी० सिंह की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक काम किया था कि उन लोगों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की थी। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि चूंकि उनमें अधिकांश लोग बिहार, यू० पी०, बंगाल, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से हैं, डी० डी० ए० में इनकी समस्याओं की चर्चा करने वाला कोई नहीं है। इनका वोट तो लेते हैं, एम० एल० ए० बनते हैं, मगर उसके बाद इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों से पांच लाख से अधिक लोग दिल्ली में स्थाई रूप से इन झुग्गी-झोंपड़ियों में बसते हैं, उन राज्यों से एक सदस्य लोक सभा का और एक सदस्य राज्य सभा का होना चाहिए, इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए डी० डी० ए० में। यह मेरा सुझाव है।

महोदय, दिल्ली में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, यहां निबंधित संस्थाओं द्वारा जो स्कूल खुलते हैं, उनको डी० डी० ए० जमीन देती है और ये सोसाइटी वाले बड़े पैमाने पर उस जमीन का दुरुपयोग करते हैं। स्कूल खोलते हैं, उसकी इतनी ऊंची फीस रखते हैं कि गरीब के बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं होता है और जमीन का दुरुपयोग होता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसकी जांच कराए कि उन लोगों को जहां-जहां जमीनें दी गई हैं, वहां-वहां उन जमीनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं?

महोदय, पिछले दिनों मैं ब्लू लाइन बसों के संबंध में इस सदन में ज़ीरो आंवर में एक सवाल उठाया था और बताया था कि रोज़ इन बसों से मौतें हो रही हैं। दिल्ली में यातायात की जो व्यवस्था है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। सड़कों पर बड़ी भीड़ चल रही है। महोदय, अगर इस व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो सड़कों पर जो मौतें हो रही हैं, उनमें काफी वृद्धि

होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए इस पर भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of my party, I totally support the Bill. This gives us an opportunity to highlight some of the problems relating to the development of Delhi. The Bill is intended to elect representatives to the DDA. A major problem of Delhi today is the pollution which a study by the Centre for Environment had characterised as 'nothing short of murder'. Delhi with its 27 lakh vehicles is going to attain 30 lakh vehicles by 2000 AD and there is no concerted effort to check the dangerous emissions from these vehicles and impounding of such vehicles. The traffic jungle and the reckless driving of the Blue Line buses are causing half a dozen deaths and half a dozen accidents every day. And we are talking of the shortage of petroleum products, etc., costing our exchequer about Rs. 27,000 crores in foreign exchange. But we are not discouraging proliferation of vehicles, either of two-wheelers or three-wheelers or four-wheelers. The Supreme Court had recently intervened in the matter and suggested two methods. One is about introduction of Maruti vans instead of the three-wheelers or two wheelers. The second method that the Supreme Court had suggested was an experiment with propane by which pollution could be reduced. The Supreme Court had also ordered closure of 39,000 factories. Of course, a part of this order was implemented. And a part of it is likely to be implemented very shortly.

It is going to have about ten lakh workers thrown into the streets. The Government had taken a very casual attitude towards this matter. We had discussed this matter recently in this House. I think it should take prompt measures to somehow convince the Supreme Court and see to it that these prople are not thrown out. If at all these industrial units have to be changed or relocated or they are given to option to set up some other non-polluting industries, it should be done in a phased manner and not so suddenly as the Supreme Court or the Government intends to do it. The other thing is that the industry should be provided with sufficient money and proper technology and knowhow so that the polluting units update their technology and see to it that pollution is curtailed.

Sir, the greatest concentration of wealth is in Delhi because it is the Capital, the Central Government pours a lot of money into it, there is a lot of commerce and trade here, maybe there is also a lot of black money here and there is money passing from various States to this Capital city. It is one of the richest parts of this country.

But, ironically, Sir, 40% of the population of Delhi lives in *jhuggis* or, what we call, the slums. The National Commission on Urbanisation has said that the worst slums are in Delhi and their living conditions are horrible and inhuman. They need to be improved. Their roads are to be improved. Their water supply is to be improved. Electricity is to be provided and better housing is to be provided to these people. We have to see that their houses are regularised, to recognise their right of settlement and to save them from thugs and some of the unscrupulous politicians who extract money from these poor people.

The next comes land use and management. Land has become a goldmine in Delhi. A lot of money is put on real estate. Speculation is going on and the middle class suffers because of all this. Building norms are violated. Regulations are violated. The authorities turn a blind

eye to all these things. Regular encroachment on Government land is going on. While the *jhuggis* are demolished, these encroachments are looked at with a lot of kindness. A through inquiry into the whole issue has to be conducted. An estimated Three hundred crores of rupees as electricity charges are not being paid by some of the people who are privileged. This has to be looked into. There is a move for privatisation of garbage collection, privatisation of water supply, privatisation of electricity supply, etc. All these things will help those people who have got the means to pay and the poor are going to suffer because of this drive for privatisation.

The last point that I would like to mention is that there are two prestigious hospitals in the city but the poor people are not served in any of these health-care organisations. Therefore, we see this spectacle of so many infectious diseases spreading in this city. The recent Dengue fever is one very vocal example of this state of affairs here.

So, if the DDA with its new members that are going to be added to it, can look after all these things, it would be a very nice thing for Delhi.

Thank you.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास संशोधन अधिनियम, 1996 का मैं समर्थन करता हूं। इसमें दो बहुत ही मामूली संशोधन हैं। एक तो यह है कि कैपिटल सिटी का नाम बदला गया है और दूसरा यह है कि तीन प्रतिनिधि दिल्ली विधान सभा से चुने जाएंगे डी० डी० ए० में ताकि उसका जनवादी स्वरूप डी० डी० ए० में जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से कायम किया जाए। तो इस व्यवस्था का मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, डी० डी० ए० की जब स्थापना हुई थी तो उसका मकसद यह था कि दिल्ली का विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। अभी जो स्थिति दिल्ली के अन्दर है वह आप देखेंगे कि योजनाबद्ध तरीके से इसका विकास नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर डीडीए की स्थापना हुई है डीडीए अगर कारगर तरीके से अपनी भूमिका को निभा नहीं रहा है तो मेरा सुझाव होगा कि डीडीए को कारगर बनाने के लिए आप उपाय करें। आप ऐसी व्यवस्था करें कि डीडीए अपने दायित्व का सही तरीके से पालन करते हुए दिल्ली का चहुंमुखी विकास कर सके।

महोदय, डीडीए में भ्रष्टाचार की भी शिकायत है, उसमें नौकरशाही भी चलती है, तो मेरा सुझाव होगा कि आप डीडीए की समीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या डीडीए के पदाधिकारी इस भ्रष्टचार में लिप्त हैं या नहीं। अगर वे लिप्त हैं तो उनकी लालफीताशाही से, नौकरशाही से डीडीए को मुक्त करने की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि डीडीए की जमीन पर बड़ी पैमाने पर दूसरे लोगों का कब्जा है, गैर-कानूनी तरीके से कब्जा है और डीडीए इस अतिक्रमण को, नाजायज कब्जे को हटाने में समर्थ नहीं है, तो वह समर्थ क्यों नहीं है जबकि इसकी तो उसके पास शक्ति है? लेकिन दुख की बात यह है कि डीडीए को यह भी पता नहीं है कि उनकी जमीन कहां-कहां पर है। जमीन के बारे में सही जानकारी डीडीए अथारिटी को तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है। मैंने दिल्ली के एक इलाके के संबंध में प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं-नहीं, वह डीडीए की जमीन नहीं है। इस संबंध में मैंने चेयरमैन साहब को लिखकर दिया कि यह उत्तर सही नहीं है इसकी छानबीन की जाए। इससे स्पष्ट है कि डीडीए के पदाधिकारी अपनी जमीन का भी सही आकलन अपने पास नहीं रखे हुए हैं। कुछ लोग पावर आफ अटार्नी लिखकर सरकारी जमीन को बेच देते हैं। इस तरह की घटनाएं दिल्ली में घट रही है और डीडीए उन घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली का विकास करना है तो डीडीए का जो कार्यकलाप है, इसके जो कार्य हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। इनमें बगैर सुधार किए आप दिल्ली का योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं कर सकते हैं। मुझे एक जगह की जानकारी है कि मंडावली में सब्जी मण्डी के लिए डीडीए ने जमीन अलाट की और अलाटी लोगों ने छोटी-छोटी दुकानें बना ली परन्तु वहां के प्रभावशाली लोगों ने उनको तोड़ दिया और डीडीए अथारिटी कहती है कि हम क्या करें। अगर डीडीए इतनी कमजोर है कि वह अपनी जमीन को जिसे वह अलाट करती है उसको सुरक्षा भी प्रदान न करें तो डीडीए दिल्ली के विकास के काम को कैसे कर सकती है? मैं इसकी कमजोरी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं

ताकि डीडीए की जो कमजोरी है उसको दूर किया जा सके। हमारे साथियों ने बताया कि अनाधिकृत कलोनियां बन गईं। यहां पर ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड दोनों तरह की कलोनियां हैं। इन कलोनियों में पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है और जब बिजली और पानी नहीं है तो इस दिल्ली में विकास की बात क्या करनी है? वहां जो लोग ऑथराइज या अनऑथराइज तरीके से बस गये हैं, उनको आपको बसाना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो वे कहां जायेंगे? जो बस्तियां बस गई हैं, उन सब को उजाड़ दिया जायेगा तो गरीब लोग कहां जायेंगे? वे चीखे जा रहे हैं, उनके लिए पीने का पानी, बिजली जैसी आवश्यक चीजों की आपूर्ति होनी चाहिए। ओखला, मंडावली और इस तरह की अनेक बस्तियां और कलोनियां हैं जिन कालोनियों में पेयजल और बिजली की व्यवस्था नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन बस्तियों का सर्वे कराकर डीडीए के माध्यम से थोड़ा आप भी ध्यान दीजिये इसलिए कि डीडीए बहुत विशाल हाथी है। यह बहुत धीरे-धीरे चलता है, इसकी रफ्तार को आपको तेज करना पड़ेगा। इसको चुस्त, दुरूस्त, ठीक-ठाक करना पड़ेगा। इसका सर्वे कराकर जो आम लोगों को सहूलियतें मिलनी चाहियें पानी, बिजली इनको तो मुहैया कराइये, सफाई की व्यवस्था कीजिये ताकि दिल्ली जैसी राजधानी में भी जो तरह-तरह की महामारी फैलती है वह न फैल सके जिसकी चर्चा अभी माननीय सदस्य कर चुके है। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया आदि-आदि तो उसकी चर्चा मै नहीं करना चाहता। यह पूरे देश को विदित है हम, आप और सभी जानते हैं। अंत में मैं यह पूछना चाहूंगा कि किस तरह से दिल्ली का विकास किया जायेगा? सही मायनों में यह भारत की राजधानी है। किसी साथी को एतराज हो सकता है कि यह मुगलों का शहर नहीं है पांडवों का बनाया हुआ है। पांडवों का बनाया हुआ तो इन्द्रप्रस्थ है। दिल्ली दिल्ली के रूप में भारत की एक पुरानी राजधानी है, पहले भी थी, अभी है, आगे भी रहेगी इसको क्या इसी तरह रखा जायेगा? यह इस देश के हित में, दिल्ली के हित में होगा, यह भारत की शानोशौकत होगी कि दिल्ली एक साफसुथरा विकसित शहर हो। अंत में मैं यह कहकर खत्म करना चाहूंगा कि दिल्ली का विकास संभव नहीं है, यह मेरी मजबूरी समझिये इसलिए कि अभी एक लाख मजदूर बेकार हो चुके हैं और 31 जनवरी, 1997 को 668 कारखाने बन्द होने जा रहे हैं, प्रदूषण फैल गया है दिल्ली में, इस नाम पर। मैं मानता हूं कि दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। मैं तो दिल्ली में कम रहता हूं लेकिन कभी-कभी किसी मित्र के यहां जाना पड़ता है तो गाड़ी पांच-सात मिनट के लिए रुक जाती है और इतना धुंआ निकलता है बस से कि आंख लहरने लगती है, जलन होने लगती है नाक से दम घुटने लगता है, यह प्रदूषण की हालत है। दिल्ली राजधानी है, चाहे पॉल्यूशन का सवाल हो, बिजली पानी का सवाल हो, सफाई का सवाल हो, दुर्घटना का सवाल हो, यह आम बात हो गई है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए डीडीए को भी सबल बनाना होगा, कारगर बनाना होगा, साथ ही साथ और भी काम करना पड़ेगा और सारे कारखानों को अगर दिल्ली से हटा देंगे तो आज के औद्योगिक युग में दिल्ली में क्या रह जायेगा? मैं मंत्री जी से और सदन से भी कहना चाहूंगा कि तब दिल्ली में में क्या रह जायेगा? इसलिए आप हटाइये लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली की बगल में कीजिये जहां पर आपके कल-कारखाने भी हों, जिनमें लोगों को रोजगार भी मिले और पोल्यूशन से भी दिल्ली की जनता को बचाया जा सके। इस तरह की एक योजना बनाकर इस दिल्ली के विकास करने की दिशा में आप बढ़ें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं जो सुझाव दिये गये हैं उन पर अमल करना, उनको कार्यान्वित करना दिल्ली की जनता के हित में आवश्यक है और दिल्ली के विकास के हित में है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार और हमारी सरकार के माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं इस दिशा में कोई कारगर कदम उठायेंगे और डीडीए को भी कारगर बनाने में अपनी पहल करेंगे ताकि दिल्ली का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से हो सके और दिल्ली में रहने वाले गरीब और अमीर सभी तरह के लोगों को सारी नागरिक सुविधाएं मिल सकें, इसकी गारंटी करें, तब दिल्ली का सही मायनों में विकास किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri Ish Dutt Yadav.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, now, it is my turn because chance has to be given alternatively.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Narayanasamy, I know that. At the beginning there was no name from your party. I think you have given your name afterwards and, hence, your name is here after Shri Ish Dutt Yadav.

SHRI ISH DUTT YADAV (Uttar

Pradesh): Mr. Narayanasamy, you will get an opportunity.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will not take more than five minutes. I have to attend a meeting.

SHRI ISH DUTT YADAV: Sir, I will take only three minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): बोलिये।

श्री ईश दत्त यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996, जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका कुछ आपत्तियों के साथ समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसमें तीन संशोधन प्रस्तावित हैं। एक तो "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे, इसका मैं समर्थन करता हूं। दूसरा "प्रशासक" शब्द जहां जहां आता है, वहां उपराज्यपाल शब्द रखा जाएगा, इसका भी मैं पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन जो इसमें प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन प्रतिनिधि जिनका निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, यह अच्छी बात है। इनमें से दो सदस्य सत्तारूढ़ दल से होंगे और एक विपक्षी दल से होगा। इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि सत्तारूढ़ दल कौन होगा और विपक्षी दल कौन होगा, जिसको विधान सभा के अध्यक्ष मान्यता देंगे। मान्यवर, मुझे इस पर आपत्ति है। मैं यह चाहता हूं कि यह प्रतिबंध इस संस्था पर नहीं रहना चाहिये। विधान सभा से तीन प्रतिनिधि चुने जाने चाहियें, सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से तीन प्रतिनिधि चुने जाने चाहियें, चाहे वह सत्तारुढ़ दल के हों, चाहे मुख्य विपक्षी दल के हों, चाहे किसी भी विपक्षी दल के हों, चाहे निर्दलीय हों, यह प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये, शर्त नहीं लगानी चाहिये। इस तरह से बाकी दलों के लोग नहीं चुने जा सकते हैं। कोई निर्दलीय सदस्य जो वहां जा कर काम कर सकता है, वह नहीं चुना जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को एक संस्था से दूसरी संस्था में भेजने के इस देश में अनेक कानून बने हुए है लेकिन मेरी जानकारी में इस तरह का प्रतिबंध कहीं भी किसी कानून में नहीं है। इसलिए इस प्रतिबंध को माननीय मंत्री जी को हटा देना चाहिये। विधान सभा से तीन सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचित होने चाहियें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन यह है, कोहली जी ने भी कहा और हमारे दूसरे माननीय मित्रों ने भी कहा कि लोक सभा और राज्य सभा से भी कम से कम एक एक प्रतिनिधि दिल्ली विकास प्राधिकरण में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये। यह मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से।

मान्यवर, दिल्ली देश की राजधानी है। लगभग एक करोड़ के करीब लोग यहां बसते हैं। दिन-प्रति-दिन आबादी बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूं सरकार की तरफ से इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई योजना नहीं है, इच्छा शक्ति का भी अभाव लगता है। अगर इसी तरह से बेतहाशा आबादी बढ़ती गई तो दिल्ली एक अरब लोगों की राजधानी है और दुनियां के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, दिल्ली जो इस बड़े देश की बड़ी राजधानी है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बस की दुर्घटनाएं बढ़ती बढ़ती जा रही हैं। रोज़ अखबारों में पढ़िये। एक दिन इसी सदन में मुझे स्मरण है वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि जनता दरबार में जो लोग समस्याएं ले कर आते हैं वह अपहरण की और बलात्कार की समस्याएं होती हैं। दिल्ली के अन्दर बलात्कार और अपहरण की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, गंदगी बढ़ती चली जा रही है, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। मान्यवर, जब कभी आप ट्रेन से आएं, चाहे पुरानी दिल्ली हो या नई दिल्ली हो, दिल्ली के समीप झुग्गी-झोपड़ियों का दृश्य देख लीजिये, आदमी के पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। किस तरह से उनका नारकीय जीवन व्यतीत हो रहा है, जल का अभाव है, बिजली का अभाव है, शुद्ध पेयजल और शुद्ध वायु उनको नहीं मिल पा रही है।

क्या सरकार ने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया? सरकार को चाहिए कि इन नागरिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। श्री कोहली जी की एक बात का मैं समर्थन कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि दिल्ली में अनेकों संस्थाएं है दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी है, डी०टी०सी० है, डेसू है, न जाने कितनी संस्थाएं हैं और किसी संस्था का किसी से समन्वय नहीं, किसी का किसी से तालमेल नहीं। मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था है तो इसका मुख्य कारण यह है कि एक कंट्रोल कोई नहीं है। एक व्यक्ति का या एक संस्थान का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सब के सब लोग स्वतंत्र पड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि दिल्ली खूबसूरत नगरी बने। पहले चाहे यह इन्द्रप्रस्थ रही हो, चाहे पाण्डवों के समय की राजधानी रही हो, चाहे मुगल काल की राजधानी रही

हो, लेकिन अब यह स्वतंत्र भारत की राजधानी है। इस स्वतंत्र भारत की राजधानी का स्वरूप सुन्दर होना चाहिए। एक आकर्षण होना चाहिए दिल्ली में, खूबसूरत दिल्ली होनी चाहिए, लुभावनी दिल्ली होनी चाहिए और शांतिमय दिल्ली होनी चाहिए। यह कल्पना करके काम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से और भारत की सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप एक स्ट्रांग विल पावर नहीं बनाएंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बनाएंगे—दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली के लोगों को सुखी रखने के लिए दिल्ली के सौन्दर्यीकरण के लिए और दिल्ली को प्रदूषण से, अपराध से, गंदगी से, सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए—तो इस तरह के संशोधनों से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा हूं लेकिन पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करूंगा कि जो आपने प्रतिबंध लगा दिया कि केवल रूलिंग पार्टी का जाएगा, विपक्ष का जाएगा तो बाकी विधान सभा के लोग क्या करेंगे, क्या उसमें योग्य लोग नहीं होंगे जो डीडीए में जाकर अपने अच्छे विचारों को दे सकें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी लोग क्षमा करेंगे। मैं देखता हूं कि वे परिश्रम कम करना चाहते हैं। जो डिपार्टमेंट से बनकर बिल चला आया उस पर आप जनहित की दृष्टि से गौर करें। मुझे इस पर सख्त ऐतराज है कि आपने प्रतिबंध कर दिया है कि केवल रूलिंग पार्टी का ही जाएगा, विपक्ष का ही एक जाएगा। आप विधान सभा को स्वतंत्र करिए। तीन आदमी जो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुने जाएं वे डीडीए में जाकर अपने अमूल्य सुझाव दें अपना योगदान करें डीडीए के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMAY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Lastly.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes; lastly; after Ish Dutt Yadavji.

Sir, hon. Members who have participated in the discussion on this Bill—the Member from Delhi and others—have mentioned certain points. I would not touch upon those points. I would only like to highlight two-three important things.

This is an inocuous Bill. This is an innocuous amendment. Since the 'Union Territory of Delhi' has become the 'National Capital Territory of Delhi', through this amending Bill, the words "Union Territory of Delhi" and "Administrator" are being substituted by the words "National Capital Territory of Delhi" and "Lieutenant Governor", respectively. This Bill also provides for election of three representatives from the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to the Delhi Development Authority.

Now, Sir, what is the state of affairs in the Delhi Development Authority? I agree with what the hon. Members—Kohli Saheb and others, including Ish Dutt Yadavji—have said. The DDA is being controlled by the Central Government. Then, there are various organisation, including the All-India Institute of Medical Sciences. There are also various Boards and Corporations. They are all under the control of the Central Government. Representatives of Parliament are there in these bodies. Earlier, Sir, in the DDA also, representatives of Parliament were there. I feel it is a genuine demand. I think the hon. Minister will consider this. If it is controlled by the State Government, I have no claim to it. I want to make it very clear to the hon. Minister that if it is under the control of the State Government, I cannot make a demand. Since it is controlled by the Central Government, the Members of Parliament who are coming from that area and who have go interest in the DDA, should be represented on it. This is number one.

Number two, about the state of affairs that has been prevailing in the DDA, they never care for public representation. I do not know who is controlling the DDA.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): The Lt. Governor is the Chairman.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, now he is there. I am talking about the state of affairs which was prevailing earlier. Even when Members of Parliament represented the grievances of the people, we were told that the Chairman would never meet the concerned people. That was the state of affairs. How are they able to interact with the people, and how do they try to redress the grievances of the people?

Then, there is no need to mention about corruption. Even an architect was arrested. It has been reported that money and documents worth crores of rupees were found. He was suspended, and an inquiry is going on. Looking into the quality of the construction today, especially of the DDA flats, we need not talk about engineers and others in the DDA.

Then, the DDA lands have been encroached. Even when genuine owners are there, the DDA tries to claim their lands. Unauthorised occupations are on the increased. The DDA cannot prove its ownership.

Then, a number of slums are coming up within the vicinity of the capital city. They allow people to put up their structures. Then they try to remove them. Then political pressure is brought. Thereafter, they cannot do anything. This is going on within the vicinity of even the areas where Members of Parliament and other people are living. There is encroachment, and unathorised colonies are coming up. This is going on.

Unauthorised construction is very much in Delhi. The DDA does pick and choose. It takes action against people at random without following the fixed norms and policies which have been enunciated.

Though I am glad that the Governor has become the Chairman, how will he be able to devote more time? That also has to be seen.

The public is not happy with the functioning of the DDA. It is a very hard fact. Whenever we talk to them, they say that there is no coordination—the hon. Member has mentioned this—among the various agencies. When we talk to people from the DESU or to people from the DDA, they say, "Our work is only up to this. We will not go beyond this." They do not have coordination. This very sorry state of affiars is prevailing.

I want to submit that there are three representatives of the Legislative Assembly. The ruling party and the Opposition have to be equally represented. Since political parties have agree to this with the then Home Minister, this issue need not be raised. The political parties who are represented through their members, can have a say on matters. Let us not plead the case of independents. Therefore, the ruling party and the Opposition can be represented so that they will be able to function efficiently.

Then, sir, another important aspect is this. I want to tell the hon. Minister that we have been making the claim. Why do you keep the Capital Territory of Delhi with you? There is a demand from the people of the Capital Territory to give it statehood. Why does the Central Government give some powers, and why does it take away some other powers? Why is there a mixture? By that, neither are you able to do anything, nor are they able to do anything. Only the responsibility of keeping the city clean falls squarely on the State Government, but the Central Government's share is also there. They give directions. The Chief Minister simply says that it is the Central Government's responsibility. You say that it is the State Government's responsibility. Therefore, ultimately, the people are affected. This is the state of affairs prevailing in Delhi.

If effeciency of the DDA is to be

improved, his Ministry should do a proper monitoring of the functioning of every wing of the DDA. The hon. Minister can call review meetings with the Officers to ensure efficient functioning of the DDA. The public interaction with the DDA is not much. Whenever people go there with grievances, they are not given proper response. They are rather harassed. It it a very serious state of affairs. Generally the public feels that Delhi Development Authority is a misnomer. It has, in fact, become a Delhi Destroying Authority. This is the people's perception about the DDA. Let that perception be removed from the minds of the people by actually making it function as a development agency. The hon. Ministry is a dynamic person. I hope he will ensure its efficient funtioning.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI Md. SALIM) in the Chair.]

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आप के माध्यम से मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने आधे-अधूरे संशोधनों को वापिस करके एक उचित संशोधन प्रस्तुत करें ताकि वास्तव में दिल्ली का विकास हो सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली के संदर्भ में इतनी अधिक व्यवस्थाएं दे दी हैं कि उन व्यवस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण की सर्वाधिक आलोचना की है। मंत्री महोदय की जानकारी में यह सब होना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, उचित यह होता कि सर्वोच्च न्यायालय की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए विधेयक में समुचित संशोधन लाया जाता। महोदय, यह बड़ी अजीब बात है कि हम सब न्यायपालिका की अवधारणा की चिंता तो करते हैं, उस की प्रशस्ति तो गाते हैं, लेकिन उस के द्वारा जब कभी भी स्वस्थ व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उन की चिंता हमें नहीं रहती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहुंगा कि ऐसा विधेयक लाने में उन्हें क्या आपत्ति थी ताकि दिल्ली एक सुंदर शहर बन पाता, दिल्ली प्रदूषण-मुक्त हो पाता, दिल्ली के पार्क सही हो पाते और दिल्ली में आवास की सही व्यवस्था हो पाती? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1979 से जिन लोगों ने दिल्ली में भवन प्राप्त करने के लिए अपने पंजीकरण कराए, उन्हें आज तक भवन नहीं दिए गए और उन में से लगभग 1 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए हैं। यह स्थिति क्यों आई? क्यों सर्वोच्च न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ता है?

महोदय, वैसे तो जो संशोधन आया है, वह अपने आप में बहुत सीधा-साधा है। सच बात यह है कि यह संशोधन किसी भी तरह के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता ही नहीं देता। दिल्ली विकास प्राधिकरण में 18 सदस्य हैं जिनमें से दो चुनकर आते हैं दिल्ली नगर निगम से। अब दिल्ली की नगर निगम तो पता नहीं कब आएगी, कब चुनाव होंगे और कब उस के प्रतिनिधि आएंगे? और तीन आने हैं दिल्ली विधान सभा से। अब ये तीन प्रतिनिधि किस प्रकार से दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सब से बड़ी समस्या यह है कि उस पर नौकरशाही हावी है और जहां नौकरशाही हावी होती है, वहां भ्रष्टाचार होता है। मंत्री महोदय जानते हैं कि इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जन-प्रतिनिधि कर सकते हैं। यही भारत का संविधान है और यही भारत के संविधान की आत्मा है। तो अब संविधान की इस आत्मा का अपहरण करने की चेष्टा क्यों की जा रही है? यह कहना कि पिछली सरकार या किसी सरकार से कभी तीन प्रतिनिधियों की बातें हो गयीं, लेकिन क्या तीन प्रतिनिधि लाने से दिल्ली विकास प्राधिकरण को लोकतांत्रिक स्वरूप मिल जाएगा? सीधा-सादा सवाल है हमारा मंत्री महोदय से अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए, उसमें जवाबदेही लाने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं? जो प्रावधान वह लाए हैं तीन प्रतिनिधि लाकर के, उससे तो कोई जवाबदेही बनने वाली है नहीं। किसी भी सूरत में जवाबदेही नहीं बन सकती और जब जवाबदेही नहीं बन सकती तो ऐसे संशोधन लाने का अर्थ क्या होता है?

महोदय, आवश्यकता तो इस बात की थी कि दिल्ली शहर सरकार के हाथों सौंपा जाता। आवश्यकता तो इस बात की थी कि दिल्ली शहर के विकास में दिल्ली सरकार को पूरा विश्वास में लिया जाता और दिल्ली के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें पूरी तरह से विश्वास में लिया जाता, लेकिन आप पूरी तरह से तो छोड़िए, जो आप तीन प्रतिनिधि लाना चाहते हैं उसमें भी राजनैतिक भेदभाव कर रहे हैं। यह अनुचित है, पूर्ण रूप से अनुचित है। दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, मंत्री महोदय, जनता और वह सामान्य जनता यह नहीं जानती कि दिल्ली शहर के विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, वह तो समझती है कि जो प्रतिनिधि उसने चुनकर भेजा है वही

उसके पार्कों की रक्षा करेगा, वही उसे प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगा, वही पानी की व्यवस्था करेगा, वही सड़कों की व्यवस्था करेगा। यह एक अजीब सवाल है, जनता प्रतिनिधि चुनती है अपने विकास के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन नौकरशाही हावी हो जाती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी, आज भी हम उसी व्यवस्था पर चल रहे हैं जाने अनजाने। कहीं जानबूझकर चलते हैं, कहीं अनजाने में चलते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जब बार बार कहते हैं कि वह एक ऐसा स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, मुझे वह बताएं कि यह जो वह संशोधन ला रहे हैं उससे जनता के प्रति जवाबदेही कैसे बनेगी? दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही कैसे बनेगी? अगर नहीं बनेगी तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या भारत सरकार उत्तरदायी है? अगर भारत सरकार उत्तरदायी है तो भारत सरकार की यह स्थिति बहुत साफ तौर पर देश के सामने अब आ जानी चाहिए कि दिल्ली की जो अव्यवस्था है उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, यहां की मंत्रि-परिषद उत्तरदायी है।

महोदय, बात बहुत साफ है। हमारे अन्य मित्रों ने कहा, सत्ता पक्ष के मित्रों ने कहा कि दिल्ली में आतंकवाद है, दिल्ली में अपहरण है, बलात्कार है, तो उसके लिए प्रधान मंत्री उत्तरदायी क्यों नहीं है फिर? दिल्ली में झुग्गी हैं, झोपड़ियां हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? जनता के प्रतिनिधि अगर उत्तरदायी नहीं बनाए जाएंगे तो क्या नौकरशाही उत्तरदायी है? अगर नौकरशाही उत्तरदायी है तो वे कौन नौकरशाह हैं, उनके नाम भी सामने आने चाहिएं। यह अब टलने वाली बात नहीं है। जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनेगी, उनसे चाहेगी कि यह प्रतिनिधि उसकी व्यवस्था करें, उसकी रक्षा करें, उसकी समस्याओं का समाधान खोजें। यही है लोकतंत्र की आत्मा और इसी से कुछ देश का विकास संभव होगा। मंत्री महोदय, दिल्ली में बहुत समस्याएं हैं। सारी समस्याओं की चर्चा यहां हो चुकी है। मैं एक सिद्धांतगत-बात आपसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी के राज्य क्षेत्र की चर्चा इसमें की गई है, इसके बारे में अनेक परिकल्पनाएं सामने आ चुकी हैं। मंत्री जी चले गए शायद।

श्री ईशदत्त यादव: मंत्री जी बैठे हैं। जालप्पा जी बैठे हैं। एक मंत्री अभी हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: अच्छा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? इसके संदर्भ में अनेक परिकल्पनाएं चल चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरठ तक का क्षेत्र राजधानी के राज्य क्षेत्र में आ जाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा का कुछ हिस्सा इसमें आएगा, लेकिन दिल्ली का वह हिस्सा या नोयडा सरीखा जो दिल्ली के नजदीक का हिस्सा है वह दिल्ली का राज्यक्षेत्र क्यों नहीं बन सकता?

श्री मोहम्मद आजम खान (उत्तर प्रदेश): लखनऊ क्यों नहीं? ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं नोयडा की बात कर रहा हूं, लखनऊ की बात नहीं कर रहा। नोयडा और लखनऊ में जो अंतर है, आजम भाई जानते हैं उस बात को। यह मैंने परिकल्पना बताई दिल्ली के राजधानी राज्य-क्षेत्र के बारे में, जो आई है और मैंने उन्हीं की चर्चा की है। मेरा उस पर कोई स्पष्ट मत नहीं है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं, कल्पनाएं प्रचलित हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमाकरण से पहले कृपया समय-सीमा का ध्यान रखें।

श्री नरेन्द्र मोहन: समय-सीमा के बारे में तो यह है कि हमारे दल की ओर से दूसरा नम्बर मुझे दिया गया है जिस पर मैं बोल रहा हूं और मैं समझता हूं कि समय-सीमा के अंदर ही बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ऐसा है कि आपकी पार्टी के लिए 22 मिनट का समय निर्धारित था। 27 मिनट कोहली जी बोल चुके हैं, माइनस पांच मिनट से आप बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: ऐसा है तो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर दो मिनट का समय मुझे और दे दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप दस मिनट पहले ही बोल चुके हैं, दो मिनट और बोल लीजिए।

श्री नरेन्द्र मोहन: धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी।

एक मुख्य बात जो देखने को मिली है, मैं उसके ऊपर माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा और वह यह है कि आए दिन दिल्ली सरकार और डी० डी० ए० के बीच एक टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब देखना यह होगा कि यह टकराव की स्थिति कैसे ठीक हो? अनेक छोटी-छोटी बातों पर टकराव हुआ है, बड़ी

बातों पर तो टकराव है ही, छोटी-छोटी बातों पर टकराव रहता है। दिल्ली का मुख्य मंत्री कुछ और सोचता है, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, और उपराज्यपाल का दृष्टिकोण कुछ दूसरा रहता है। यह मतभेद कैसे समाप्त हो, इसकी कोई न कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए अन्यथा विकास के कार्य में बाधाएं ही बाधाएं उत्पन्न होंगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो और समस्याएं हैं, वे तो हैं ही लेकिन जो आपसी कलह है नौकरशाही के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, उसके कारण भी दिल्ली के विकास में बाधा पहुंची है और यह बाधा तब समाप्त हो सकती है जब दिल्ली सरकार को पूर्ण रूप से हम जन-प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दें, केवल तभी विकास संभव हो पाएगा। धन्यवाद।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I seek only one clarification in respect of the proposed clause (f) in sub-section 3 of the Act. The last portion of that clause reads, ".....two shall be from among the ruling party and one from the party in opposition to the Government:". There is an Explanation stating, "For the purposes of this clause, "ruling party" and "party in opposition to Government" shall mean the ruling party and the party in opposition to the Government recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi."

Sir, the Speaker will recognise only one party as the opposition party. But there will be other parties also which may not be called "opposition parties". They may be small parties. The legislators have got the right to vote. But the right to contest is denied to them. That has to be considered. It amounts to denial of the democratic right of legislators to contest in the election. This anomaly or riqour that is imposed in the Explanation should be removed and an opportunity should be given to all the legislators, all those who are eligible to vote and to contest, to succeed. The opportunity should be given to them.

With these few words, I conclude my speech.

श्री मोहम्मद आज़म खान: जो रिप्रेज़ेंटेशन की बात आई है, रूलिंग पार्टी और अपोजीशन की, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी एक बार फिर उसका निरीक्षण करा लें ...(**व्यवधान**)...सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस पर चैलेंज होगा ...(**व्यवधान**)...यह बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है।

श्री मोहम्मद सलीम: आप बैठ जाइए, मंत्री जी बोल रहे हैं।

DR. U. VENKATESWARLU: Several Members have said that. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): He requests you to keep that point in view when you reply. *(Interruptions)*

DR. U. VENKATESWARLU: Sir, I am thankful to all the hon. Members who have participated in this discussion on the Amendment Bill that has been brought before this House as has been passed by the Lok Sabha.

Sir, scheme-wise, it has got a limited scope of replacing the earlier three members from the Metropolitan Council by the three members from the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. I will explain as to how these events have come up. Before that, I would like to say something which is not directly connected with the present amendment. I can understand the anxiety that has been expressed by several hon. Members. I can understand the concern that has been expressed by various Members about Delhi and about the issues relating to Delhi, right from the encroachments that have been takin place, right from the authorised and unauthorised colonies that have been coming up in Delhi, the slum conditions that are prevailing in Delhi, the traffic congestion, population growth and various other issues which

have been paralysing almost the normal living of the people in Delhi. Sir, what this particular generation has acquired in Delhi—clean and green city— is not going to be handed over to the successor in future. That is a fact. Various hon. Members, while participating in the debate, have expressed the view as to how disproportionately Delhi is growing. Delhi is growing not only in length and breadth but also vertically in most of these parts. How is the pressure of population affecting the minimum services that are already there? Is the growth of population much ahead of the infrastructural development or is the infrastructural development following the population growth? These are some of the issues that have been mentioned. I am not going to hesitate to accept the fact that the living conditions in most parts of Delhi are in bad shape, and they are going to be worse in the coming years. I have to address myself to most of these problems. The issues that have been projected by most of the Members will really give a lot of information to me and will enable me to discharge my functions as a Minister more effectively and I would be in a position to look after the welfare of Delhiites better in future. Sir, there are so many problems. For example, pollution, environmental degradation, traffic congestion, inadequate provision of the basic amenities, growth in the number of accident, thereby making the life of Delhiites miserable. These are some of the major problems that have been projected by the hon. Members, including the housing problem in Delhi. Sir, this Government, during the past mix months, have taken certain steps. I will explain them one by one, and thereafter, I will come to the main part of the amendment that has been moved. This Government has taken certain steps, keeping most of these issues in view. The first thing that I have taken up after my taking over charge is the clearance of the MRTS project which has been pending for the last 22 years. This will certainly give some relief to Delhiites I think the people of Delhi must be happy to know that the particular project, which was conceived 22 years ago, has ben cleared in the month of September by this Government. Sir, this project will cost Rs. 4,852 crores. Its completion will require Rs. 8,200 crores. This project will provide 53 kms long rail track for the people of Delhi. So, with the completion of this project, most of the road traffic can be relieved. Once the road traffic is relieved the number of accidents will also get reduced. The movement on the streets will also be easier. This Government has the will and this project has been cleared by this particular Government. This Government is committed to do some service to Delhi proper, which is a capital city. The present population is something like more than one crore. It has exceeded 1.1 crores. By the turn of the century the population is likely to be 1.25 crores. As some hon. Members have suggested, the number of vehicles on the roads in Delhi is something like 27 lakhs. For every 3.8 persons there is one vehicle in Delhi. You can very well imagine the kind to pollution that is being caused by these vehicles. This is our anxiety. Keeping in view all these things, this project has been cleared by this Government. You will also be happy to know that OECF loan from Japan has also been cleared. We have signed an agreement only on the 6th of this month. This agreement has been signed only five days ago. We are getting a total amount of 14.76 billion Japanese yen, which is equivalent to Rs. 478.78 crores, with an interest rate of only 2.3%. This is for the year 1996-97 alone. We hope that this project will be commenced from June next year and most of these problems will be solved.

Though there are several minute suggestions made by the hon. Members, the second main aspect which the hon. Members have raised is NCR. Since the National Capital Territory was getting so congested and highly populous, a plan had been concieved as early as 1962 to

carve out some areas from the neighbouring States and to develop a National Capital Region, where the infrastructure should be developed so that the population could be spread over a larger area. This NCR was conceived long back. After taking over charge of this Ministry I had convened a meeting of the Chief Ministers of Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan in the month of September, 1996. The hon. Prime Minister had inaugurated that meeting. We had discussed various issues. It requires as much as Rs. 30,000 crores immediately for the development of minimum infrastructure. The hon. Prime Minister had constituted a separate sub-committee in that meeting. It is headed by me. The Finance Ministers of the four neighbouring States are the other members. We are going to look into the issue as to how we can mobilise the resources and develop the infrastructure so that the population of Delhi can be spread over the whole National Capital Region and so that the population is not confined only to the National Capital Territory. This is another thing which has been done by this Government.

The third aspect is this. You will be happy to know this. Slum problem is such a big problem in this city. As the hon. Members have pointed out, there are as many as 1,071 slum colonies around Delhi, whether they are authorised or unauthorised. Most of these colonies are not having the minimum basic amenities. Even if they are having, they are substandard facilities. These are the colonies which are to be addressed. As a preliminary step this Government has sponsored a new scheme, that is, the Prime Minister's Slum Development Scheme. This Scheme has been launched by the Prime Minister from Kanpur in the month of August, 1996. A sum of Rs. 250 crores was earmarked for utilisation in this financial year to solve some of the slum problems. I am not telling you that we are going to solve all the problems of the slums with this sum of Rs. 250 crores. A beginning has been made by the Government to solve some of the slum problems. Delhi is also getting quite a sizeable sum, besides other States. The slum problems are being addressed as such by the Government and this Government is looking after all these things.

6.00 P.M.

The fourth major area is housing shortage. Housing shortage is not a small problem. So far as the DDA is concerned, basically it is a facilitator. The DDA has constructed 2.58 lakh houses on its own and it has facilitated construction of 2.50 lakh houses by providing plots to individuals. The DDA has provided 2.40 lakh dwelling units to JJ resettlement colonies. The number of dwelling units constructed on plots allotted to Cooperative Group Housing Societies is 1.90 lakhs. The number of dwelling units through Rohini Scheme is 0.85 lakhs. The DDA by itself and through all these agencies has facilitated constructions of 10.23 lakh dwelling units so far. Still there is a deficiency of five lakh units. A survey was conducted in 1990-91. There was a deficiency of 2.39 lakh units by 1991. After 1991, 50,000 units were added to the deficiency every year. In these five years the deficiency has increased by 2.50 lakhs units. Altogether, there is a deficiency of five lakh dwelling units in this city. That is the problem. Keeping in view this particular thing, I had organised a National Housing Seminar in the month of October for three days. I had invited all the public representatives who were dealing with housing, urban development and municipal administration from all the States. As many as 25 hon. Ministers from various States had participated in the Seminar. The concerned senior officials of the level of a Secretary also participated in it. I had invited NGOs and private builders also. All these people participated in the Seminar. We discussed several aspects of the housing problem in the country. There is a deficiency of 30 million housing units in the country. That is the problem. Keeping in view the seriousness of this problem I convened the meeting to discuss this problem. We are at it. The Government is taking

up this issue very seriously. The hon. Members have raised many issues. I am trying to touch upon three or four major issues. One point was raised is that recently the Supreme Court issued certain directives but those directives were not looked into by this Government. Recently, the Supreme Court has directed the Government to shift all the hazardous and polluting industries outside Delhi. In the first instance, 168 units were supposed to be shifted by the 30th November, 1996. The Government of India has filed an affidavit projecting various dimensions of this problem. In the second cluster, 513 units are to be shifted by the 31st January, 1997 and in the third culster more than 40 units are to be shifted by the 28th February, 1997. These are all hazardous units. In addition to this, 43,000 non-conforming units are also to be shifted from Delhi by the 31st of this month. These are the directives. The Delhi Government has constituted a committee to go into all these details. We are expecting that the report of the Committee would be with us in a few days. When I was replying to the debate in Lok Sabha I said that an all-party meeting would be convened.

A meeting of all leaders of political parties will be convened immediately after we receive this report. This will be done so that we can address these problems and discuss them. The consensus opinion will be adopted by this Government. That is as far as direction is concerned. How many houses have been vacated? How many unauthorised constructions have been demolished! These questions have also been raised here. I have the figures but it will not be worth-while giving them here. A question was raised about coordination between the Delhi Government and the Union Government. Every month I have been having meeting with the Chief Ministyer of Delhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You can write to the Member and give him the detailed information.

DR. U. VENKATESWARLU: An hon. Member raised a question about congestion. He said that in 1976, 2.2 lakh hectares of land was found to be surplus. But so far only 15,000 hectares have been procured. This is the main reason for congestion. The Urban Land Ceiling Act was enacted in 1976. Over the past 20 years we have seen that the performance of this Act has been dismal. It is no secret.

We are taking up these issues. This Government is examining it. I have asked chief Ministers to send in their suggestions so that we can bring forward an elaborate and comprehensive amendments to the Urban Land Ceiling Act. Only then can we make this Act more effective and the problem of congestion in some parts of the city can also be solved. We are actually at it. Another issue that has been raised is about corruption in DDA. I am not going to claim that DDA is totally free of curruption. In the past three years, about 26 corruption cases have been detected. Four people have been suspended. Other people are being tried at different levels. Punishing a Government officer is very difficult according to the Service Rule Book. We have to go through a lot of procedure. All these 26 people are being tried at different levels and suitable action will be taken. I will not hesitate to take action once people are found guilty. It has been said that there is no grievance cell in DDA. I have been monitoring this issue on a monthly basis. I will not hesitate to create a grievance cell in DDA. The officers can meet once a month. They can invite public representations and these can be disposed of immediately. They can, at least, acknowledge them and send replies after looking into the case. As far as DDA is concerned, this will be done. Another issue was raised: "Why not transfer DDA to the State Government of Delhi?" The DDA was created by an enactment of Parliament. It was created by the 69th amendment of the

Constitution. It is a statutorily constituted independent body under the Government of India.

As far as other points are concerned, two issues have been raised. One is, why should we not have all the three MLAs and why should it be mentioned as two MLAs from the ruling party and one MLA from the Opposition Party. This is the main issue. Sir, this Bill has been prepared after consulting the Delhi Government and after a great deal of discussion and consideration at various levels, including the Cabinet.

Sir, the purpose behind this provision was to give wider representation and expression to the views of the people's representatives representing different shades of opinion of the different parties. The proposed amendment will lead to omission of this provision and spirit which will give rise to the possibility of all the three representatives of the Delhi Legislative Assembly being from the ruling party itself and denying representation to the Opposition Parties. So far as the second amendment is concerned it may be mentioned that the authority is basically a decision making body and comprises ten members excluding the proposed three Members of the Delhi Legislative Assembly. At the stage of formulating the proposal for composition of the authority, the issue was dealt with in detail, in consultation with the various ministries, departments including the Ministry of Home Affairs. Sir, here as far as MPs are concerned, MPs are already Members of the Advisory Council. For the past three years the Advisory Council has not met. But soon after I took charge we had a meeting in the month of November and in the month of February we are going to have another meeting of the Advisory Council. So whatever has been discussed, whatever suggestions have been made will be considered in the Board meeting. The consensus opinion is that it should not be a larger body. Sir, as far as Opposition and the ruling party are concerned, earlier, on 5.6.1995, the then Home Minister had convened a meeting of the leaders and the Chief Minister of Delhi and the Lieutenant-Governor also attended that meeting. In this meeting a consensus opinion was arrived at. The minutes of the meeting are with me. The Chief Minister of the Government of National Capital Territory of Delhi reiterated his earlier view that the authority should have three Members of the Legislative Assembly to be elected from among Members of the Legislative Assembly and two elected representatives from the MCD as per the earlier package. He added that out of the three Members of Legislative Assembly proposed by him, two could be from the ruling party and one could be from the main Opposition party elected on the basis of single transferable vote, adopting the principle of proportional representation. This view was endorsed even by the Lieutenant-Governor also. This meeting was chaired by the then Home Minister and attended by the Minister of Urban Affairs, the Lieutenant-Governor, the Chief Minister of NCT and other Secretaries. This is the consensus arrived at the meeting.

श्री मोहम्मद आजम खान: मैं अर्ज करूंगा कि बहस की हमारी स्प्रिट तो हो सकती है, कन्वेंशन हो सकता है लेकिन यह लीगल प्रोसीजर नहीं है। हम जिस सदन में बैठे हैं यहां सिर्फ प्रेजीडेंट आफ इंडिया को नामिनेट करने का अधिकार है। बाकी के जितने भी सदस्य आते हैं सब इलेक्ट होकर आते हैं यहां तक कि आपकी चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति भी नामिनेट नहीं होंगे इलेक्ट होंगे, न कि आपोजीशन और रूलिंग के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है। यह तो हमारे पूरे सेट अप के खिलाफ है। हमारी स्प्रिट ही खत्म हो जाएगी, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा सेट अप तो मुमकिन है ही नहीं। देश की किसी विधान सभा में पहले से लेकर आज तक और लोकसभा में कहीं पहले इस तरह का कोई मिसाल मिलती ही नहीं। अगर कभी किसी मीटिंग में ऐसा सोचा गया तो उसका मतलब यह नहीं कि यह रूल आफ ला हो जाए। इसलिए मैंने कहा था कि इस बात की आशंका है कि कोई भी व्यक्ति अदालत में चला जाएगा। यह चेलेंज हो जाएगा। यह

खत्म हो जाएगा। बेकार ह्यूमिलिएशन हो जाएगा सरकार को।

श्री ओम प्रकाश कोहली: उसको लीगली एग्जामिन करवा लिया है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The question which the hon. Member is asking is whether you have consulted the Law Ministry or not.

DR. U. VENKATESWARLU: I am going on record...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): In the Bangalore Development Authority also, we have got the same system. So far nobody has challenged it.

DR. U. VENKATESWARLU: After arriving at this consensus...*(Interruptions)*...

श्री ईश दत्त यादव: उपसभाध्यक्ष जी, एक मिनट क्षमा करेंगे...(व्यवधान) यह केवल लैफ्टिनेंट गवर्नर की राय है। होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें लैफ्टिनेंट गवर्नर की राय रही कि दो रूलिंग पार्टी से रहें और एक विपक्ष से रहे, तो क्या यह सदन लैफ्टिनेंट गवर्नर की राय को मानने के लिए बाध्य है? क्यों नहीं आप लॉ डिपार्टमेंट से इस को एग्जामिन करा रहे हैं? यह तो अनकंस्टीट्यूशनल हो जाएगा?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Minister, you have just now said that consensus was arrived at in the meeting. You have said that the Chief Minister of Delhi had proposed it and the Lieutenant-Governor supported it. But what about the consensus? There must be some other leaders also in that meeting.

DR. U. VENKATESWARLU: After this meeting, the matter went to the Cabinet at that time. The then Cabinet approved it. I had put up this proposal before the present Cabinet, which comprises 13 political parties. It had also approved it. Later on, the issue was referred to the Law Ministry. It had also approved it. After all this, this Bill is brought forth before this House. The former Chief Minister of Delhi who belongs to BJP had proposed it. The Lieutenant-Governor of Delhi had supported it. The then Cabinet had approved it. The present Cabinet had also approved it. After this, I referred this matter to the Law Ministry. It gave its clearance. So, with the concurrence of the Law Ministry only we have brought forth this Bill before this House.

श्री ओम प्रकाश कोहली: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्वायंट जो पहले यहां उठ चुका है उसकी तरफ फिर से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप विधान सभा के 3 प्रतिनिधि डी०डी०ए० पर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं और विधान सभा के किसी भी सदस्य का चुनाव कंटेस्ट करने का अधिकार आप कैसे छीन लेंगे? मान लीजिए विधान सभा में कोई इंडीपेंडेंट मैंबर है या कोई बहुत छोटी सी पार्टी का सदस्य है, उसके अधिकार को आप कैसे छीन लेंगे? If these three persons are going to be the representatives of the legislative assembly, not of the respective political parties, then how can you snatch away the right of the independents and Members of smaller groups. That is may question?

DR. U. VENKATESWARLU: Sir, this matter has also been examined. The explanation of the Law Ministry is there in the Bill itself which says, "...for the purpose of this clause, ruling party and party in opposition to the Government shall mean the ruling party and the party in opposition to the Government recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi."

Sir, this is mainly to give representation to a major group so that the voice of the people, through the

major groups, will be at least heard in the DDA. As such this issue has also been referred to the Law Ministry and it has given its clearance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Minister, you have made it clear and said that representation should be there from both the sides. Here the question is something different. You have said about the ruling party and the major opposition parties. Then how do you debar a Member who is an independent or Members belonging to minor opposition parties?

DR. U. VENKATESWARLU: The only explanation that I can offer at this stage is that these issues have been discussed in the meeting referred to. In that meeting, a consensus was arrived at. That is the thing. That consensus was approved by the then Cabinet and also by the present Cabinet. The issue has received the clearance from the Law Ministry also.

श्री ईश दत्त यादव: सर, एक मिनिट का टाइम दे दीजिए। आप ने सही प्रश्न किया मंत्री जी से। यह पहले कैबिनेट में हुआ और नई गवर्नमेंट की कैबिनेट में भी विचार किया गया। गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, उस में भी विचार हुआ और ला डिपार्टमेंट ने भी आप को राय दे दी। लेकिन क्या यह अन-कांस्टीट्यूशनल नहीं होगा कि 90 लोगों का एक सदन है दिल्ली विधान सभा।

श्री ओम प्रकाश: 70 का है।

श्री ईश दत्त यादव: 70 सदस्यों का सदन है और इन 70 सदस्यों में केवल रूलिंग पार्टी और मेजर अपोजीशन पार्टी को ही डी०डी०ए० में आने का मौका मिलेगा। फिर छोटे दल होंगे, निर्दलीय होंगे, उन को मौका नहीं मिलेगा। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सब लोगों की राय के बावजूद भी क्या यह अन-कांस्टीट्यूशनल नहीं होगा? क्या आप इस को एप्रेशिएट कर रहे हैं? और अगर यह अन-कांस्टीट्यूशनल होने वाला है तो एक बार आप इस बिल को पुनः वापिस ले लीजिए। ला डिपार्टमेंट को भेजिए और फिर सदन के सामने ले आइए।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, can I make a point here?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Yes, yes.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, my point is very simple. I am saying that there is some confusion on this issue. I am also not clear in my mind about it—the ruling party, the opposition parties, the independents, this and that. What I am requesting is this. Let us get the Bill passed today and let the Minister give us an assurance that he will look into the matter, he will talk to the Law Ministry and, if necessary, he will make the amendment.

श्री ईश दत्त यादव: यह ठीक है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: बिल्कुल ठीक है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Minister, there is a suggestion. You need not elaborate on that. If you find that there is some weight in it, you apply your mind.

DR. U. VENKATESWARLU: Sir, as has been suggested by our hon. Member, Dr. Biplab Dasgupta, there is no hesitation in once again seeking a clarification from the Law Minister, after the Bill is passed. I will lay that opinion of the Law Ministry on the Table of the House.

SHRI ISH DUTT YADAV: No, no. It is not necessary to table it, Mr. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): yes, yes. You need not table it.

DR. U. VENKATESWARLU: All right, Sir. I will refer it. So, Sir, we have had a lengthy discussion on this Bill. I am really thankful once again to all the hon. Members who have participated in the discussion and extended valuable suggestions. As I mentioned right in the beginning, the issues pertaining to the fuctioning of the DDA and other issues, will be looked into.

With these words, I request that the

Bill be passed.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अब लगता है डी०डी०ए० का कुछ सुधार होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now I will put the motion to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Development Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. U. VENKATESWARLU: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 13th December, 1996.